स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रधान मंत्री का भाषण
15 अगस्त, 2008

मेरे प्यारे देशवासियों, भाइयों, बहनों और प्यारे बच्चों,

आज़ादी की सालगिरह के इस खुशी के मौके पर आप सबको बधाई।

आज का दिन सभी भारतीयों के लिए एक मुबारक दिन है।

आज के दिन हम उन सभी लोगों की कुर्बानी को याद करते हैं जिन्होंने महात्मा गांधी के नेतृत्व में विदेशी हुकूमत से हमें आज़ादी दिलाने की लड़ाई लड़ी।

आज हम उन सभी लोगों की कड़ी मेहनत और लगन को याद करते हैं जिन्होंने एक आज़ाद और नया भारत बनाने में अपनी जान की बाजी लगा दी। आज हमें इस काम में अपने आपको फिर से लगाना है।

आज हम अपने किसानों, कामगारों और शिक्षकों को याद करते हैं। हम अपनी फौज के जवानों को याद करते हैं जो बर्फीले पहाड़ों, रेगिस्तानों, जंगलों, समुद्री किनारों और समुंदर के बीच हमारी सरहदों की हिफाजत कर रहे हैं।

भाइयों और बहनों,

चार साल पहले, आज के दिन, यहां आपके सामने खड़े होकर मैंने आपको अपनी सरकार के एक नया भारत बनाने के सपने के बारे में बताया था।

मैंने आपसे कहा था कि हम एक ऐसा भारत बनाना चाहते हैं:

जिसमें सबको इंसाफ मिले और जहां इंसानियत और भाईचारा हो;

एक ऐसा भारत जिसमें सभी लोगों को बराबर समझा जाए;

एक ऐसा भारत जो खुशहाल हो;

एक ऐसा भारत जिसमें अमन-चैन हो;

एक ऐसा भारत जिसमें हरेक को अपनी सलाहियत के मुताबिक काम मिल सके, और वह अपना भविष्य बना सके।

एक ऐसा भारत जो secular हो, जिसमें भेदभाव और नाइंसाफी न हो।

एक ऐसा भारत जिसमें विविधता में एकता हो।

ऐसा भारत बनाने की हमारी पूरी कोशिश रही है।

भाइयों और बहनों,

चार साल पहले मैंने यहां खड़े होकर आप से कहा था कि मुझे वादे करने नहीं बल्कि निभाने हैं।

राष्ट्रीय न्यूनतम साझा कार्यक्रम पर अमल करना हमारा वादा था;

'ग्रामीण भारत' में नई उम्मीद जगाना हमारा वादा था;

अपने आर्थिक और सामाजिक विकास में सबको साथ लेकर चलना हमारा वादा था;

भारत को दुनिया के देशों के बीच उसकी सही जगह दिलाना हमारा वादा था;

हमारी सरकार ने इन सभी वादों को पूरा करने की ईमानदारी से कोशिश की है।

हमने **ग्रामीण भारत में एक नई उम्मीद** जगाई हैः

हमने ग्रामीण इलाकों में सेहत, शिक्षा, बिजली, सड़क, आवास और सिंचाई के लिए निवेश बहुत बढ़ा दिया है।

राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के जरिए हम खेती के लिए 25,000 करोड़ रुपये लगा रहे हैं;

कर्ज के बोझ से दबे अपने किसान भाइयों को राहत देने के लिए हमने लगभग 71,000 करोड़ रुपये का बैंकों से लिया गया कर्ज माफ किया है;

पिछले चार सालों में हमने खेती के लिए बैंकों द्वारा दिए गए कर्ज की रकम 81,000 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 2,25,000 करोड़ रुपये कर दी है और ऐसे कर्ज पर ब्याज दर भी घटाई है;

किसानों की आर्थिक हालत सुधारने के लिए हमने अनाजों की खरीद कीमतों में काफी बढ़ोत्तरी की है, जो गेहूं के लिए 50% तथा धान के लिए 30% है;

चावल, गेहूँ और दालों की पैदावार बढ़ाने के लिए **राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन** बनाया गया है;

सिंचाई, जलाशयों, बारिश से सिंचाई वाले इलाकों और बाढ़ रोकने पर हमने खास तवज्जो दी है;

ग्रामीण इलाकों में ज्यादा रकम लगाने और किसानों को कर्ज से राहत देने की हमारी कोशिश से हमारी खेती मजबूत हुई है;

कृषि में निवेश बढ़ रहा है और इस क्षेत्र में लगभग एक दशक, खासकर 1998 से 2004 तक, के ठहराव के बाद फिर तेज़ी आई है। वर्ष 2007-08 में खाद्यान्नों, कपास और चीनी का रिकार्ड उत्पादन हुआ है।

हमारे खेत फिर से हरे-भरे दिखाई दे रहे हैं। हमारे अनाज भंडार फिर से भरने लगे हैं। हमारे किसानों में अपने भविष्य और अपनी खुशहाली को लेकर फिर से उम्मीद जगी है।

भाइयों और बहनों,

मैंने अपनी ज़िन्दगी के पहले दस साल एक छोटे से गांव में बिताए, जहां न बिजली थी, न पीने के पानी का सही इंतजाम, न कोई डाक्टर, न सड़क, न ही फोन। मुझे मीलों पैदल चलकर स्कूल जाना पड़ता था। मुझे रात में मिट्‌टी के तेल के लैम्प की हल्की रोशनी में पढ़ाई करनी पड़ती थी। आजादी मिलने के बाद ग्रामीण इलाकों में काफी विकास हुआ है फिर भी जिस तरह की ज़िन्दगी मैंने बचपन में गुजारी थी वैसी ही ज़िन्दगी अभी भी हमारे देश में बहुत से लोग गुजार रहे हैं।

यही वजह है कि जब हमारी सरकार बनी, हमने देहातों में बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए **'भारत निर्माण'** की शुरुआत की। हमारी सरकार का ग्रामीण भारत को सुधारने का पक्का इरादा है। इन चार सालों में हमने अहम पहलें की हैं। मुझे यकीन है कि हमारी कोशिशों से एक नया खुशहाल भारत ज़रूर बनेगा।

मेरे प्यारे देशवासियों,

चार साल पहले मैंने अपनी सरकार की सात प्राथमिकताओं या **"सात सूत्रों"** के बारे में आपको बताया था। ये हैं - खेती, पानी, शिक्षा, सेहत, रोजगार, शहरी नवीकरण और बुनियादी ढांचे की मजबूती।

इन सभी क्षेत्रों में हमने अहम पहलें की हैं। मैं खेती की तरक्की और किसानों की खुशहाली के लिए की गई कोशिशों के बारे में आपको पहले ही बता चुका हूँ।

दूसरी सबसे अहम तरक्की बुनियादी ढांचे को मजबूत करने में हुई है। रेलवे के विकास में नई तेज़ी आई है। नई सड़कें बनाई जा रही हैं। नए बन्दरगाह और हवाई अड्‌डे भी बनाए जा रहे हैं।

हमारी आबादी का एक बड़ा हिस्सा अब शहरों में रहता है। **जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी मिशन** के तहत शहरों की तरक्की और उन्हें नई शक्ल देने के लिए काफी सरमाया मुहैया कराया जा रहा है।

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत गांवों में सेहत से संबंधित सरकारी सेवाओं को बढ़ाया जा रहा है।

एक ऐसे आदमी की हैसियत से जिसने अपनी पेशेवर ज़िन्दगी की शुरुआत शिक्षक के तौर पर की, मुझे यह कहते हुए फख्र है कि हमारी सरकार देश में शिक्षा की तरक्की पर खास तवज्जो दे रही है। प्राथमिक, माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा में - सभी levels पर - सरकारी फण्ड बहुत बढ़ा दिया गया है।

हमने **सर्व शिक्षा अभियान** को मजबूत किया है। Mid-day Meal Programme का सभी जिलों में मिडिल स्तर तक विस्तार किया गया है और इस स्कीम के तहत लगभग 14 करोड़ बच्चों को स्कूलों में दोपहर का खाना दिया जा रहा है।

हम 6,000 नए और बहुत अच्छे मॉडल स्कूल स्थापित कर रहे हैं जो सबकी पहुँच में होंगे। हरेक ब्लॉक में, कम-से-कम एक ऐसा स्कूल होगा। पिछड़े जिलों में 373 नए कालेज खोले जा रहे हैं। हम 30 नई यूनिवर्सिटियां, 8 नए IITs, 7 नए IIMs, 20 नए IIITs, 5 नए भारतीय विज्ञान संस्थान, 2 Planning और Architecture के School, 10 NITs, और 1000 नए Polytechnic भी खोल रहे हैं।

मैंने ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना को **"राष्ट्रीय शिक्षा योजना"** कहा है। हम चाहते हैं कि शिक्षा हमारे समाज के हर तबके की पहुँच में हो। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग और अल्पसंख्यक परिवारों के बच्चों की पहुँच - हरेक बच्चे की पहुँच चाहे वह लड़का हो या लड़की - आधुनिक शिक्षा तक होनी चाहिए।

हमारी सरकार ने बच्चों की शिक्षा के लिए वज़ीफों की कई योजनाएं चलाई हैं। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग और अल्पसंख्यक परिवारों के बच्चों के लिए प्रि-मैट्रिक और पोस्ट-मैट्रिक वज़ीफों की योजनाएं चलाई जा रही हैं। इन तबकों के होशियार बच्चों के लिए खास वज़ीफे भी शुरू किए गए हैं। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के छात्रों को विदेशों में पढ़ाई के लिए वज़ीफे दिए जा रहे हैं। आर्थिक रूप से कमजोर तबकों के बच्चों और विकलांग बच्चों के लिए भी राष्ट्रीय स्तर की merit-cum-means scholarships मंजूर की गई हैं।

हमने एक नया Skill Development Mission कायम किया है जो प्रधान मंत्री की देखरेख में काम करेगा। सरकार एक Skill Development Corporation भी बनाएगी जिसमें हमारे नौजवानों, कामगारों और तकनीशियनों के लिए खास Training का इंतजाम किया जाएगा। इसमें निजी क्षेत्र की active भागीदारी हासिल की जाएगी।

मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि हम अपने मुस्लिम समुदाय की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक मजबूती के लिए पूरी ईमानदारी से **जस्टिस सच्चर कमेटी रिपोर्ट** की ज्यादातर सिफारिशों को लागू कर रहे हैं।

भारत तभी बदल सकता है जब हरेक भारतीय पढ़ा-लिखा हो, सबको पेटभर खाना मिले, हरेक भारतीय सेहतमंद हो और सबको अच्छा रोजगार मिले।

मैं एक ऐसा नया भारत देखना चाहता हूँ जो वैज्ञानिक सोच रखता हो और जिसमें शिक्षा का फायदा समाज के हर तबके को मिलता हो। हमें उम्मीद है कि इस साल हम एक भारतीय राकेट, **'चंद्रयान'**, चांद पर भेजेंगे। यह हमारे Space Programme की एक बड़ी कामयाबी होगी।

भाइयों और बहनों,

रोजगार मुहैया कराना हमारे लिए एक खास प्राथमिकता रही है। खेती, उद्योग, बुनियादी ढांचे और skill development के लिए अपनाई गई हमारी नीतियों से रोजगार को बढ़ावा मिलेगा।

हमारी प्रिय पूर्व प्रधान मंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने कहा था "गरीबी हटाओ"। हमारी नेता श्रीमती सोनिया गांधी ने हमें नारा दिया है "रोजगार बढ़ाओ"। हमारी सरकार "गरीबी" दूर करने के लिए "रोजगार" बढ़ाने के ख़ास प्रयास कर रही है।

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना हमारी सरकार की एक ऐतिहासिक पहल है। यह कार्यक्रम अब पूरे देश में चलाया जा रहा है और इसके जरिए गांव में रहने वाले सबसे ज्यादा जरूरतमंद करोड़ों लोगों को रोजी-रोटी की मदद दी जा रही है। इसका मकसद गरीबी की तीखी मार को कम करना है।

रोजगार बढ़ाने के लिए हमें कृषि, Manufacturing और बुनियादी ढांचे में ज्यादा निवेश करने की जरूरत है। हमें Industrialization की एक नई लहर लाने की जरूरत है। अगर औद्योगिक विकास का कुछ बुरा असर हमारे किसी ग्रामीण इलाके के निवासियों पर पड़ता है तो हम यह सुनिश्चित करेंगे कि इसका सही मुआवजा दिया

जाए और प्रभावित लोगों का सही पुनर्वास हो। एक नई **पुनर्वास और पुनर्स्थापना नीति** बनाई गई है और हम इस पर संसद की मंजूरी लेंगे।

हमने असंगठित क्षेत्र के कामगारों को सामाजिक सुरक्षा का फ़ायदा पहुँचाने के लिए संसद में एक Bill पेश किया है। हमारी सरकार ने आम आदमी बीमा योजना शुरू की है जिसके तहत देश के देहाती इलाकों में हरेक भूमिहीन परिवार के एक सदस्य का बीमा किया जा रहा है। गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले असंगठित क्षेत्र के कामगारों के परिवारों को स्वास्थ्य बीमा का लाभ पहुँचाने के लिए भी हमने एक Programme शुरू किया है। इंदिरा गांधी पेंशन योजना के तहत अब गरीबी रेखा से नीचे की ज़िंदगी गुजारने वाले 65 वर्ष से ज्यादा उम्र के नागरिकों को पेंशन का लाभ दिया जा रहा है।

मेरे प्यारे देशवासियों,

पिछले चार सालों में, हमारे निवेश की दर तेजी से बढ़ी है। इससे अर्थव्यवस्था के विकास की दर को बढ़ाने में मदद मिली है।

पहली बार ऐसा हुआ है कि चार सालों की मुद्दत में हमारी आर्थिक बढ़ोत्तरी 9.0% रही है। सबसे तेजी से विकास कर रही अर्थव्यवस्थाओं में भारत की जगह सबसे ऊपर के देशों में है।

लेकिन, हमारे सामने नई चुनौतियां भी हैं। हमारे सामने बढ़ती हुई मंहगाई की चुनौती है। मुझे मालूम है कि आप सभी हाल ही में कीमतों में हुई बढ़ोत्तरी से कितने परेशान हैं। इस साल जो Inflation हम देख रहे हैं वह बुनियादी तौर पर बाहरी वजहों से है। सारी दुनिया में और global markets में खाने-पीने के सामान, ईंधन और दूसरी चीजों के दाम बढ़े हैं। इन दिनों बहुत से विकासशील देशों में मंहगाई बढ़ने की दर भारत से दुगुनी है।

हमारी सरकार ने इस बात की पूरी कोशिश की है कि भारत में मंहगाई उस हद तक न बढ़े जितनी कुछ दूसरे देशों में बढ़ रही है। हमने अपने समाज के गरीब तबकों को अनाज और ईंधन की बढ़ती कीमतों के असर से बचाने के लिए भी कदम उठाए हैं। हमारी सरकार ने मिट्टी के तेल और खाद की कीमत नहीं बढ़ाई है। हमने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के ज़रिए बिकने वाले गेहूँ और चावल की कीमतों में भी बढ़ोत्तरी नहीं की है।

हम कीमतों को काबू में रखने के लिए ठोस कदम उठा रहे हैं। मैंने सभी मुख्यमंत्रियों से सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सुधार लाने और उसे मज़बूत करने का अनुरोध किया है ताकि रोज़मर्रा की ज़रूरतों की चीजें आम आदमी को उचित दर पर मिलती रहें। भारतीय रिज़र्व बैंक देश में मुद्रा-प्रसार की दर को कम कर रहा है ताकि महंगाई काबू में आ सके। इन प्रयासों को करते समय हमें यह भी ध्यान रखना होगा कि हम कुछ भी ऐसा न करें जिससे विकास की रफ़्तार को नुकसान पहुँचे।

भाइयों और बहनों

आज पिछले चार सालों में हमारी सरकार द्वारा किए गए काम के बारे में बताते हुए मैं आपसे एक वादा और करना चाहता हूँ। हमारी सरकार ने बहुत कुछ किया है लेकिन साथ ही साथ हमें अहसास है कि अब भी बहुत कुछ करना बाकी है। कुपोषण की समस्या हमारे लिए एक कलंक है जिसको हमें हर हाल में दूर करना है। हरेक बच्चे तक अच्छी शिक्षा पहुँचाने और सभी नागरिकों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए भी हम पूरा प्रयास करते रहेंगे। महिलाओं को बराबरी का दर्जा देने और उनके आर्थिक और सामाजिक सशक्तिकरण के लिए की गई अपनी पहलों को हमें और आगे बढ़ाना है। मेरा आपसे वादा है कि देश की तरक्की और खुशहाली के लिए हमारी कोशिश लगातार जारी रहेगी। हम हरेक क्षेत्र में भारत को नई ऊँचाइयों पर ले जाने के लिए मेहनत करते रहेंगे।

भाइयों और बहनों,

हमें अपनी **ऊर्जा** की समस्या का मुस्तकिल हल ढूंढ़ने के लिए आधुनिक साइंस और टेक्नोलॉजी का सहारा लेना होगा। हमारे पास तेल और गैस के भंडार कम हैं। हमें ऊर्जा के दूसरे source ढूंढ़ने होंगे। मैं चाहता हूँ कि हमारे वैज्ञानिक और इंजीनियर ऐसे तरीकों को खोजें जिनसे हम सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बायो-गैस और ऊर्जा के दूसरे sources का बेहतर इस्तेमाल कर सकें।

भुखमरी से निजात पाने और सभी के लिए रोजगार मुहैया कराने के लिए हमारी अर्थव्यवस्था हर साल कम से कम 10 फीसदी की दर से बढ़नी चाहिए। देश की तरक्की के लिए, हमारे उद्योगों और कृषि के विकास के लिए, ऊर्जा, ख़ासकर बिजली एक बुनियादी जरूरत है।

सारी दुनिया में यह समझ बढ़ रही है कि ऊर्जा सुरक्षा और मौसम में बदलाव की चुनौती से निपटने के लिए परमाणु ऊर्जा का इस्तेमाल ज़रूरी है। यह एक साफ, पर्यावरण के अनुकूल और कभी खत्म न होने वाला ऊर्जा source है।

भारत के पास विश्व स्तर के परमाणु वैज्ञानिक और टेक्नालाजिस्ट हैं। इन्होंने मुश्किलों के बावजूद परमाणु ऊर्जा क्षमता का विकास किया है। लेकिन कुछ ऐसी कठिनाइयां हैं जिनकी वजह से हमारे ऊर्जा कार्यक्रम में रुकावट आ रही है। हमारा यूरेनियम का उत्पादन हमारी ज़रूरतों के लिए काफी नहीं है। हमारा यूरेनियम उतना अच्छा भी नहीं है जितना दूसरे उत्पादकों का है। कई मुल्कों ने भारत के साथ परमाणु साजो-सामान और परमाणु टेक्नालाजी के व्यापार पर रोक भी लगा रखी है। इन सभी वजहों से हमारे परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम पर बुरा असर पड़ा है।

जिस परमाणु करार के लिए हम दुनिया के बड़े-बड़े देशों के साथ बातचीत कर रहे हैं उससे भारत पर लगी पाबंदियां खत्म होंगी। दोहरे इस्तेमाल में आने वाली technology और साजो-सामान में व्यापार के नए मौके हमारे सामने आएंगे और हमारे देश के industrialization में तेजी आएगी। इस करार से हमें अपने किसानों, दस्तकारों, व्यापार में लगे लोगों और उद्योगों की बिजली की ज़रूरतों को पूरा करने में मदद मिलेगी।

भाइयों और बहनों,

चार साल पहले मैंने आपसे कहा था कि अच्छा शासन मुहैया कराना हमारे सामने एक अहम् चुनौती है। हमने सरकार को पारदर्शी, कुशल और जवाबदेह बनाने के लिए कई कदम उठाए हैं। **सूचना का अधिकार कानून** एक ऐसा ही बड़ा कदम था। हमने सरकार के काम-काज को सुधारने और उसमें नए तरीके अपनाने के लिए भी पहल की है। **राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस कार्यक्रम** से अब सभी नागरिकों के लिए सरकार की तमाम एजेंसियों के साथ संपर्क करना आसान हो जाएगा।

हमने छठें Pay Commission की रिपोर्ट की जांच पूरी कर ली है। सरकारी कर्मचारियों की जितनी तनख्वाहें बढ़ाने की सिफ़ारिश कमीशन ने की थी, हमने उससे भी ज्यादा तनख्वाहें बढ़ाई हैं। ऐसा करते वक़्त हमने अपनी सेनाओं और para-military forces और हमारी civil services में नीचे के स्तर पर काम करने वाले सरकारी कर्मचारियों के हितों और भलाई का ख़ास ख्याल रखा है। यह सरकार को कार्य कुशल बनाने के लिए एक और कदम है।

हमें सरकार के हर स्तर पर और सुधार लाने की ज़रूरत है। हम सरकारी स्कूल, सरकारी अस्पताल और दूसरी सार्वजनिक सेवाओं को बेहतर बनाना चाहते हैं। शासन को decentralize करने और उसमें सुधार लाने में पंचायती राज संस्थाओं की अहम भूमिका होगी। हमें उनके प्रशासनिक और वित्तीय अधिकार बढ़ाने होंगे। मेरी राज्य सरकारों से अपील है कि सरकार के काम को बेहतर बनाने के लिए वह हर मुमकिन कोशिश करें और केन्द्र सरकार की पहलों में हमारी मदद करें।

मेरे प्यारे देशवासियों,

दहशतगर्दी, उग्रवाद, सांप्रदायिकता और कट्टरता हमारे देश की एकता और अखण्डता के लिए बड़ी चुनौतियां बनकर उभरे हैं। बंगलौर, अहमदाबाद, जयपुर और देश के दूसरे हिस्सों में हाल ही में जो आतंकवादी हमले हुए हैं उनसे सारे देश को परेशानी है। इस तरह के वहशियाना हमलों की निन्दा करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं हैं। दशहतगर्दी के शिकार हुए लोगों का दुख और दर्द मैं समझ सकता हूँ। ऐसे परिवारों को राहत पहुंचाने और उनके Rehabilitation के लिए भारत सरकार ठोस कदम उठाएगी।

हमारे सुरक्षा बल और खुफिया एजेंसियां कठिन हालात में इस समस्या से जिस लगन के साथ जूझ रहे हैं उसके लिए मैं उनकी सराहना करता हूं। मैं मानता हूं कि दहशतगर्दी से निपटने के लिए हमें Intelligence Agencies और Police को और मजबूत करना होगा।

हम अपनी खुफिया एजेंसियों, पुलिस और सुरक्षा बलों के कामकाज का जायजा लेंगे और उन्हें इस चुनौती का सामना करने में सक्षम बनाने के लिए हर जरूरी कदम उठाएंगे। जो भी संसाधन जरूरी होंगे उन्हें मुहैया कराया जाएगा। जितनी manpower की जरूरत होगी, हम मुहैया करायेंगे। इस समस्या से निपटने का हमारा इरादा पक्का है।

मैं राज्य सरकारों, सभी राजनैतिक दलों, civil society groups और सामाजिक और धार्मिक रहनुमाओं से गुज़ारिश करता हूं कि वे दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए हमें अपना सहयोग दें।

भाइयों और बहनों,

मुझे पूरा विश्वास है कि हम इन चुनौतियों का बखूबी मुकाबला कर पाएंगे। लेकिन इसके लिए कड़ी मेहनत की और एकजुट होकर आगे बढ़ने की जरूरत है। इसके लिए

सहमति की राजनीति चाहिए न कि टकराव की राजनीति। हमें अपने मतभेद दूर करने के लिए बातचीत का रास्ता अपनाने की ज़रूरत है।

एक बंटा हुआ मुल्क सांप्रदायिकता, आतंकवाद और extremism जैसी चुनौतियों का मुकाबला नहीं कर सकता है।

एक बंटा हुआ समाज पर्यावरण और इकॉलॉजी के नुकसान की चुनौती का सामना नहीं कर सकता है।

यदि हम लोग बंटे रहेंगे तो देश में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यक तबकों का आर्थिक और सामाजिक विकास मुमकिन नहीं हो पाएगा।

भाइयों और बहनों,

मैंने कई मौकों पर कहा है कि मुझे विकास में इलाकाई अंसतुलन की समस्या की बहुत फिक्र है। हमारे देश के कुछ हिस्से दूसरे हिस्सों की बनिस्बत ज्यादा तरक्की कर रहे हैं और कुछ पीछे रह गए हैं। यह असंतुलन काफी वक्त से चला आ रहा है। हमें यह देखना होगा कि पिछड़े हुए सूबे जल्दी से आगे आ जाएं।

हमें पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास पर विशेष ध्यान देना होगा। हमारी सरकार ने पूर्वोत्तर राज्यों और जम्मू-कश्मीर में सरकारी निवेश काफी बढ़ाया है। हम इन इलाकों में तरक्की और रोजगार के लिए बुनियादी ढांचे और शिक्षा में ज्यादा रकम लगा रहे हैं।

जम्मू-कश्मीर और North-East में विकास के लिए अमन-चैन कायम करना बहुत ज़रूरी है। इन इलाकों में शांति कायम करने के लिए हमने बहुत सी पहलें की हैं। इस सिलसिले में हमारी कोशिश आगे भी जारी रहेगी।

जम्मू और कश्मीर रियासत में हाल ही में हुई वारदातें चिन्ता का विषय हैं। मुसीबत की इस घड़ी में बंटवारे की राजनीति हमें कहीं का नहीं रखेगी। मैं सभी राजनैतिक पार्टियों से अपील करता हूं कि वे जम्मू-कश्मीर के भावी हितों का ख्याल रखें और रियासत के मसलों का स्थायी हल तलाशने के लिए मिल-जुल कर काम करें।

श्री अमर नाथ का पवित्र धाम तमाम भारतीयों को एक साथ मिलकर आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। यह धाम हमारी secular परंपरा की एक बेहतरीन मिसाल है जहाँ बरसों से हिंदू यात्रियों की देखभाल उनके मुसलमान भाई करते रहे हैं। इस पवित्र स्थान से जुड़े मुद्दे, खासकर यात्रियों को अच्छी से अच्छी सुविधाएं मुहैया कराने के लिए प्रबंध, आपसी सद्‌भावना और शांतिपूर्ण वातावरण पैदा करने से ही हल हो सकते हैं। धर्म के नाम पर लोगों को बांटने से ये मसले और भी पेचीदा हो सकते हैं और उससे देश की एकता और अखण्डता भी खतरे में पड़ सकती है। मैं जम्मू और कश्मीर की जनता से अपील करता हूँ कि राज्य में अमन और शांति बहाल करने में हमारा साथ दें। मेरा यह यकीन है कि हर एक मसले का हल बातचीत से और शांतिपूर्ण तरीके अपनाकर ही हो सकता है।

भाइयों और बहनों,

हमारे प्राचीन हिमालय के पर्यावरण को खतरा है। अगर हिमालय के ग्लेशियर पिघले तो हमारी पवित्र नदियों में पानी कम हो जाएगा। मौसम में बदलाव का बुरा असर हमारी अर्थव्यवस्था पर कई तरह से पड़ सकता है। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हमारे कुछ समुद्र के किनारे वाले इलाके भी डूब सकते हैं। बारिश के मौसम की कैफियत बदल सकती है। इन खतरों से निपटने के लिए कारगर उपायों की जरूरत है। इस सिलसिले में सरकार द्वारा सही नीतियां बनाने के लिए भी एक राष्ट्रीय सहमति की जरूरत है।

हमारी सरकार ने जलवायु परिवर्तन पर एक राष्ट्रीय कार्यनीति बनाई है। जिसमें बताया गया है कि हम किस तरह के काम करने और रहने के तरीकों को अपनाएं और अपने कुदरती संसाधनों के साथ किस तरह से पेश आएं ताकि हमारा कार्बन एमिशन सीमित रह सके और पर्यावरण सुरक्षित रहे।

प्यारे देशवासियों,

South Asia क्षेत्र में हमारा मक़सद एक शांतिपूर्ण, स्थिर और खुशहाल पड़ोस का है। हम अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा को बनाए रखते हुए अपने देश और क्षेत्र में सामाजिक और आर्थिक विकास की रफ्तार तेज करना चाहते हैं। हमारी विदेश-नीति इन्हीं उसूलों पर आधारित रही है।

हम अपने सभी पड़ोसियों का भला चाहते हैं। हम अपने पड़ोस, खासकर भूटान, नेपाल और पाकिस्तान में लोकतांत्रिक ताकतों के मजबूत होने का स्वागत करते हैं।

काबुल स्थित भारतीय दूतावास में हाल ही में हुए बम धमाकों से हमारी अपने पड़ोसी मुल्क के साथ रिश्ते सामान्य करने की कोशिशों पर बुरा असर पड़ा है। हमारे क्षेत्र में अमन कायम करने के हमारे प्रयास भी इस से प्रभावित हुए हैं। मैंने निजी तौर पर अपनी निराशा और चिंता पाकिस्तान सरकार को जता दी है।

दहशतगर्दी के मसले का हल निकाले बगैर, दोनों देशों के लोगों की अमन-चैन से रहने की हमारी ख्वाहिश पूरी नहीं हो सकेगी। शांति के लिए जो कदम हम उठाना चाहते हैं, वह भी नहीं उठा पाएंगे। दहशतगर्द और उनकी मदद करने वाले लोग भारत और पाकिस्तान दोनों देशों के अवाम के, दोनों देशों के बीच बढ़ रही दोस्ती के और शांति प्रक्रिया के दुश्मन हैं। हमें उनको शिकस्त देनी होगी।

पिछले साल में हमने दुनिया की बड़ी ताक़तों, दक्षिण अमरीकी देशों, अरब देशों और अफ्रीकी देशों के साथ अपने संबंध और मज़बूत किए हैं। अपने राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखते हुए इस दिशा में हमारा प्रयास ज़ारी रहेगा।

आज दुनिया हमें सम्मान के साथ एक ऐसे देश के रूप में देखती है जो तेज़ी से तरक्की कर रहा है। तमाम देशों में रहने वाले भारतीय मूल के लोग हर तरह के कारोबार में लगे हैं और उनकी सलाहियत का लोहा दुनिया भर में माना जा रहा है। हमें उनकी कामयाबियों से प्रेरणा मिलती है। दुनिया को भारत से उम्मीद है कि वह दुनिया के मुल्कों में अपनी सही जगह हासिल करेगा। हमारे लिए यह एक बेहतरीन मौका है।

हम दुनिया के मुल्कों में अपनी सही जगह फिर से पाने के लिए बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन उस मुकाम को पाने के लिए हमें अभी काफी मेहनत करनी होगी। हमें उन सभी चुनौतियों का मुकाबला करना होगा जिनका मैंने अभी जिक्र किया है। हमें कोशिश करनी होगी कि विभिन्न राजनैतिक पार्टियाँ, हमारे समाज के सभी तबके और सभी समुदाय, मिल-जुल कर और एक जुट होकर काम करें।

हमें अपने कुदरती और वित्तीय संसाधनों का सूझ-बूझ के साथ इस्तेमाल करना होगा। आने वाली पीढ़ियों के प्रति हमारी जवाबदेही है। हम केवल अपने लिए ही नहीं सोच सकते। हम सिर्फ एक दिन से दूसरे दिन, एक साल से दूसरे साल या एक चुनाव से अगले चुनाव तक अपनी सोच के दायरे को सीमित नहीं रख सकते। हमें अपने बच्चों, उनके बच्चों और आने वाली पीढ़ियों की भलाई और खुशहाली के बारे में भी सोचना होगा।

अगर हम एक देश के रूप में मिल जुल कर काम करने का प्रण करें, मेहनत करें और अपने सभी लोगों की भलाई का ख्याल रखें, तो ऐसा कोई भी काम नहीं है जिसे हम नहीं कर सकते हैं।

आइए, आज हम तय करें कि हम एक रहेंगे, और देश की एकता और अखंडता को मजबूत करने और अपने सपनों का एक नया भारत बनाने के अपने इरादे पर हमेशा कायम रहेंगे।

प्यारे बच्चों मेरे साथ मिलकर तीन बार बोलिए -

जय हिन्द ।

जय हिन्द ।

जय हिन्द ।

***